Losses suffered by FCI

1615. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of FOOD be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2132 given in the Rajya Sabha on the 17th December, 1993 and state :

(a) the losses suffered by the Food Corporation of India during the last three years, year-wise as a result of damage done; and

(b) the precautionary steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The details of losses suffered by the Food Corporation of India duting the last three years as a result of damage due to theft are as under :—

Year	Amount (In lakhs)
	Rs.
1990-91	15.00
1991-92	23.38
1992-93	8.15

(b) Keeping in view the storage capacity and the prevailing local conditions, Food Corporation of India Watch and Ward staff, State Armed Police and Central Industrial Security Force are deployed to guard the Corporation's godowns.

Regular checks on outgoing and incoming vehicles are done to tally stocks with gate passes. A procedure for locking, sealing and opening of the godowns has been laid down. Services of local law enforcing agencies are also being utilised as and when required. For vulnerable depots, police patrolling is arranged Physical verification of stocks and surprise inspections of godowns are conducted on regular basis.

चीनी उत्पादक एसोसिएशनों को गन्ना-विकास के लिए दिया जाने वाला ऋण

1616. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्रीराम जेठमलानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी उत्पादक संस्थाओं को गन्ना-विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान प्रदान करती है ।

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 तक गन्ना विकास योजनाओं के लिए दी गई धनराशि का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण को लौटाने के लिए कितनी समावधि और उस पर ब्याज की कितनी दर निर्धारित की गई है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना विकास योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋणों का भुगतान नियमित रूप से होता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 तक दिए गए ऋणों की कितनी राशि का भुगतान ऋण की शर्तों के अनुसार कर दिया गया है और उस देय राशि का ब्यौरा क्या है जिसका भुगतान नहीं किया गया है;

(च) क्या यह भी सच है कि विकास योजनाओं पर धन खर्च करने के बावजूद 1990-91 की तुलना में 1992-93 में प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज कम थी; और

(छ) यदि हां, तो 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी-कितनी थी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी उपक्रमों को (और न कि चीनी उत्पादक एसोसिएशनों को) अपने कार्यचालन के क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चीनी उपक्रमों को दिए जा रहे ऋण पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर पर ब्याज लगाया जाता है । इस ऋण की वापसी

तीन वर्षों के ऋण-स्थगन के बाद चार किस्तों में करनी होती है।

(च) और (छ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गन्ने का विकास करने के लिए जिन चीनी मिलों को ऋण दिए गए थे उनके मामले में मूल राशि की वापसी देय नहीं हुई है।

(च) और (छ) 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान गन्ने की औसत पैदावार निम्नानुसार रही है :—

वर्ष	पैदावार (मीटरी टन/हेक्टेयर)
1990-91	65.40
1991-92	66.07
1992-93	63.81

इससे विदित होगा कि 1990-91 की तुलना में 1992-93 के दौरान कम पैदावार हुई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पैदावार मौसमी स्थितियों पर निर्भर करती हैं जोकि प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, गन्ने का विकास करने से संबंधित योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से सहायता गन्ने के अधीन क्षेत्र के केवल एक हिस्से को ही कवर करती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बिक्री

1617. **श्री राम जेठ मलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में गेहूं को बेचने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 के अंत तक खुले बाजार में कुल कितनी मात्रा में गेहूं बेचे जाने का विचार है;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में इस गेहूं को किस-किस दर पर बेचे जाने का विचार है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इस गेहूं को 330 रुपये प्रति क्विंटल की अधिकतम दर पर खरीदा गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो यह गेहूं किसानों से किस दर पर खरीदा गया था;

(च) क्या यह भी सच है कि इस गेहूं को खुले बाजार में बेचने से भारतीय खाद्य निगम को इस सौदे से काफी आर्थिक लाभ होने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो लक्ष्यानुसार बिक्री होने के आधार पर कितना लाभ होने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 16-2-1994 तक 2 मिलियन मीटरी टन से भी अधिक गेहूं की बिक्री कर ली गई है। चूंकि इस प्रकार की बिक्री खुले बाजार में की जाती है, इसलिए फिलहाल यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 31-3-1994 तक कितनी मात्रा की बिक्री कर ली जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को 30-4-1994 तक 3 मिलियन मीटरी टन तक गेहूं बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें खुली बिक्री के लिए गेहूं के राज्यवार, मासवार मूल्य दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों ने रबी विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 330 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन